

डॉ. मोहम्मद खलील

बनाम

राजस्थान राज्य

(2012 की आपराधिक अपील संख्या 634 आदि)

12 दिसंबर, 2012

[पी. सतशिवम और रंजन गगोई, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860 -धारा 324-एक की मृत्यु और शिकायतकर्ता के साथ-साथ अभियुक्त पक्ष के व्यक्तियों को चोटें-क्रॉस-एफ़. आई. आर.-अभियुक्त को दोषी ठहराया गया। 302 और 324 आरएलडब्ल्यू धारा 34 आई.पी. सी. निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा-तीन अभियुक्तों द्वारा अपील-आयोजित:साक्ष्य से पता चलता है कि अभियुक्त भी मृतक और शिकायतकर्ता पक्ष के हाथों सशस्त्र आक्रमण के शिकार थे-अभियुक्त पर चोटों का गैर-स्पष्टीकरण से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष ने घटना की वास्तविक उत्पत्ति को दबा दिया-अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य के दो सेट एक दूसरे के साथ असंगत होने के कारण, अभियुक्त को ऐसी विसंगति का लाभ मिलेगा-अभियुक्त को केवल अपने व्यक्तिगत कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, न कि धारा 34 की सहायता से किए गए कृत्यों के लिए। उनके व्यक्तिगत कृत्यों को देखते हुए, अपीलार्थियों को केवल दोषी ठहराया जा सकता है। 324 - उनकी सजा को घटाकर पहले से गुजर चुकी अवधि कर दिया गया।

आपराधिक मुकदमा:अभियुक्त पर चोटों का विवरण न देना-उसका प्रभाव-आयोजित:अभियुक्त पर चोटों का विवरण न देने से निष्कर्ष निकलते हैं:(1) कि अभियोजन पक्ष ने घटना की उत्पत्ति को दबा दिया है; (2) जो गवाह चोटों की उपस्थिति से इनकार करते हैं, वे अविश्वसनीय हैं; (3) कि यदि बचाव पक्ष चोटों की व्याख्या करता है, तो यह अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा करता है-गैर-

स्पष्टीकरण अधिक महत्व रखता है जहां साक्ष्य में इच्छुक या शत्रुतापूर्ण गवाह होते हैं या जहां बचाव पक्ष एक ऐसा संस्करण देता है जो अभियोजन पक्ष के साथ संभावना में प्रतिस्पर्धा करता है-हालाँकि, चोटों का गैर-स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित नहीं कर सकता है, जहां आरोपी को लगी चोटें मामूली और सतही हैं या जहां सबूत इतने स्पष्ट और ठोस हैं, कि यह गैर-स्पष्टीकरण के प्रभाव से अधिक है।

विरोधाभासी साक्ष्य-प्रभाव-जहां अभियोजन पक्ष साक्ष्य के दो सेटों का नेतृत्व करता है-प्रत्येक एक दूसरे का खंडन करता है और दूसरे पर हमला करता है, तो अभियुक्त को ऐसी स्थिति का लाभ होगा-दोनों पक्षों को उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए दोषी ठहराया जा सकता है और आम तौर पर किसी भी पक्ष को निजी बचाव का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं है।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 136-का दायरा और परिधि:अनुच्छेद 136 उन मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है जहां न्यायाधीश की गंभीर विफलता हुई है-यह अपील का अधिकार प्रदान नहीं करता है-न्यायाधीशालय अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायाधीशालय के निष्कर्षों को फिर से नहीं खोलता है, जब तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष होते हैं, तो कानून का कोई सवाल शामिल नहीं होता है और निष्कर्ष विकृत नहीं होता है।विचाराधीन घटना वर्तमान अपीलों में, दोनों पक्षों में एक व्यक्ति की मृत्यु और कुछ को चोटें आई हैं।दोनों पक्षों द्वारा क्रॉस एफ. आई. आर. दर्ज की गई।अपीलार्थी-अभियुक्त के साथ-साथ अभियुक्त 'एफ' को प्राथमिकी आर. संख्या 9011992 में शामिल किया गया था।क्रॉस-केस में छह अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया। वर्तमान मामले में ब्रलाल अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया।302 और 324 आर/डब्ल्यू।धारा 34 भा.दं.सं. सी. उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।उच्च न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।

क्रॉस-केस में अभियुक्तों पर अलग से मुकदमा चलाया गया और उन्हें ब्रलाल अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया। 3071149, 148 और भा.दं.सं. सी. 3241149। आदेश के खिलाफ अपील अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। ए-1, ए-2 और ए३ द्वारा तत्काल अपीलें की गईं।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1 अभियोजन पक्ष के मामले के विश्लेषण से साक्ष्य के दो सेट सामने आए हैं। साक्ष्य से पता चलता है कि वर्तमान अपीलों में आरोपी कुछ हद तक मृतक और उसके साथियों के हाथों सशस्त्र हमले के शिकार हैं। गवाहों के साक्ष्य से पता चलता है कि शिकायतकर्ता का दल तलवार, हॉकी स्टिक आदि से लैस था, उसने दुर्व्यवहार किया, कैदियों पर पत्थर फेंके और ए-2 और ए-4 को मारने का आह्वान किया। इसलिए, अपीलकर्ताओं का यह दावा करना उचित है कि शिकायतकर्ता समूह घटना और उन्हें हुई चोटों के लिए जिम्मेदार था। [पारस 30 और 15] [794-जी; 805-एफ-एच; 806-ए]

1.2 पीडब्लू-3, पीडब्लू-6, पीडब्लू-13 और पीडब्लू-18, चश्मदीद गवाहों ने ए४ और ए३ द्वारा प्राप्त स्वीकृत चोटों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति में, उन्हें घटना की वास्तविक उत्पत्ति को दबाने का दोषी ठहराया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने अभियोजन पक्ष के रुख का समर्थन किया, और अपने साक्ष्य पर भरोसा किया, भले ही अदालत अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर ले, गैर-सरकारी गवाहों, अर्थात् पीडब्लू 4 और 5 के बयान को देखते हुए, शिकायतकर्ता जो क्रॉस-केस में आरोपी थे, वे भी अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए प्रायोजित थे। [पारस 31 और 16] [794-हि 795-सि ¶ डि 806-सि ¶ इ]

1.3 अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्त द्वारा की गई चोटों की व्याख्या करे और स्वीकार्य सामग्री के माध्यम से घटना की उत्पत्ति को स्थापित करे। जहाँ

अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर चोटों की व्याख्या करने के लिए गिरता है, वहाँ दो परिणाम निम्नलिखित हैं: (1) कि अभियोजन पक्ष के गवाह का अपराध असत्य है और (2) कि न्यायाधीश अपीलार्थियों द्वारा ली गई याचिका की जांच करेगा। एक संदिग्ध मामले में, घटना के लगभग समय या विवाद के दौरान अभियुक्त द्वारा की गई चोटों का गैर-ऑक्सीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति है, जिससे अदालत निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकती है: " (1) कि अभियोजन पक्ष ने उत्पत्ति और घटना की उत्पत्ति को दबा दिया है और इस प्रकार सही संस्करण प्रस्तुत नहीं किया है; (2) जिन गवाहों ने अभियुक्त के व्यक्ति पर चोटों की उपस्थिति से इनकार किया है, वे सबसे अधिक भौतिक बिंदु पर झूठ बोल रहे हैं और इसलिए उनका साक्ष्य अविश्वसनीय है; (3) यदि कोई बचाव संस्करण है जो अभियुक्त के व्यक्ति पर चोटों की व्याख्या करता है तो इसे संभावित रूप से प्रस्तुत किया जाता है ताकि अभियोजन मामले पर संदेह किया जा सके। [पारस 27 और 20] [800-ए-डी; 804-डी-ई]

लक्ष्मी सिंह और अन्य. बनाम बिहार राज्य (1976) 4 एस. सी. सी. 394-पर निर्भर था।

1.4 अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के व्यक्ति पर चोटों की व्याख्या करने में चूक बहुत अधिक महत्व रखती है जहां साक्ष्य में इच्छुक या शत्रुतापूर्ण गवाह होते हैं या जहां बचाव पक्ष एक ऐसा संस्करण देता है जो अभियोजन पक्ष के साथ प्रायिकता में प्रतिस्पर्धा करता है। हालाँकि, ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ अभियोजन पक्ष द्वारा चोटों का स्पष्टीकरण न दिए जाने से अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। यह सिद्धांत वाहायह उन मामलों में लागू होता है जहां अभियुक्त को मामूली और सतही चोटें लगी हैं या जहां साक्ष्य इतना स्पष्ट और ठोस है कि चोटों की व्याख्या करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से चूक के प्रभाव से अधिक है। [पैरा 21] [800-ई-जी]

वामन और अन्य. बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 7 एससीसी 295:2011 (6)  
एस. सी. आर. 1072-पर निर्भर।

1.5 वर्तमान मामले में, यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि उसी घटना के दौरान ए-4 और ए-3 को भी चोटें आईं। वास्तव में, ए-4 को धारदार हथियार के उपयोग से गंभीर चोट लगी। हालाँकि, अभियोजन पक्ष द्वारा इन चोटों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया गया था। अभियोजन पक्ष घटना की उत्पत्ति को साबित करने में विफल रहा और वास्तव में उन्होंने इसे दबा दिया। [पैरा 27 और 19] एच [799-ई; 804-एफ]

1.6 सामग्री के विश्लेषण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत घटना के दो संस्करण एक दूसरे के साथ असंगत हैं। ऐसी स्थिति में जब अभियोजन पक्ष साक्ष्य के दो सेटों का नेतृत्व करता है, जिनमें से प्रत्येक विरोधाभासी होता है और दूसरे पर हमला करता है और इसे अविश्वसनीय दिखाता है, तो परिणाम यह होगा कि अदालत के पास कोई विश्वसनीय और भरोसेमंद सबूत नहीं बचेगा, जिस पर अभियुक्त की दोषसिद्धि आधारित हो। अभियुक्त को ऐसी स्थिति का लाभ मिलेगा। दोनों पक्षों को उनके व्यक्तिगत कृत्यों के लिए दोषी ठहराया जा सकता है और आम तौर पर किसी भी पक्ष को निजी बचाव का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं है और वे अपने-अपने कृत्यों के लिए दोषी होंगे। [पैरा 32] (806-एफ-जी, एच; 807-ए)

रघुबीर सिंह और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (2011) 12 एससीसी 235:2011 (10) एससीआर 739; कृष्णन बनाम तमिलनाडु राज्य (2006) 11 एससीसी 304:2006 (4) पूरक।एससीआर 536; बाबुला/भगवान खंडारे और अन्न बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) 10 धारा 404:2004 (6) पूरक।एस. सी. आर. 633-पर निर्भर।

1.7 ए-2 की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, उसके खिलाफ भा.दं.सं. सी. की खंड 34 लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहां तक कि स्वतंत्र गवाह भी।, पीडब्ल्यू

4 और 5 किसी भी स्पष्ट कार्य के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं। भले ही अभियोजन पक्ष के गवाहों का सबूत कि ए-2 के पास तलवार थी और पीडब्लू-3 को उसके कहने पर चोटें लगी थीं, स्वीकार किया जाता है, उसके व्यक्तिगत कार्य को देखते हुए, उसे केवल यू/एस के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। 324 भा.दं.सं. सी. और उसकी उम्र और इस तथ्य पर ध्यान दें हुए कि वह लगभग एक साल और चार महीने से हिरासत में था, सजा को पहले से गुजर चुकी अवधि में बदलकर न्यायाधीश का अंत किया जाएगा। [पारस 33 और 38 जे [807-बी; 808-एफ-जी]

1.8 ए-2-पाकिस्तान का नागरिक होने के नाते, इस अदालत के आदेश के अनुसार, रु। अपने गृह देश, यानी पाकिस्तान की यात्रा के लिए इस न्यायालय की पंजीकरण के साथ प्रतिभूति के रूप में 5 लाख। इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि आगे किसी अभिरक्षा की आवश्यकता नहीं है, पंजीकरण को ए-2 या उसके नामित व्यक्ति को उक्त राशि तुरंत वापस करने का निर्देश दिया जाता है। यह भी निर्देश दिया जाता है कि यदि अपीलकर्ता का पासपोर्ट या कोई अन्य दस्तावेज निचली निचली अदालत या भारत सरकार के किसी अन्य प्राधिकारी की हिरासत में है, तो उन्हें उसे वापस करने का निर्देश दिया जाता है और वह बिना किसी प्रतिबंध के अपने देश लौटने के लिए स्वतंत्र है। उनकी आयु और विद्या सम्बन्धी योग्यता आदि ध्यान दें में रखते हुए, इस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए, भारत सरकार के संबंधित विभाग को आवश्यक वीजा जारी करने और उनके देश में उनकी सुचारू वापसी के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 39) [809-ए-बी, सी-ईजे

1.9 ए-1 और ए-3 को स्वीकार्य सामग्री के बिना, भा.दं.सं. सी. की खंड 34 की सहायता से उनके द्वारा किए गए व्यक्तिगत कार्यों के लिए दंडित और दायित्व निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने उल्लेख किया कि इन अपीलार्थियों के पास एक पिस्तौल थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या किसी को उस पिस्तौल की गोली लगी थी और कोई विशिष्ट सबूत नहीं दिया गया था कि

गोली उनके हाथ में पी. एल. स्टोल से निकली थी।यहां तक कि पीडब्लू-3 ने भी कहा कि इन अपीलकर्ताओं ने अपनी पिस्तौल से गोलीबारी की लेकिन उस आग से किसी को चोट नहीं लगी।पीडब्लू 4 और 5 ने भी उनके द्वारा किए गए किसी भी हमले का श्रेय नहीं दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि शिकायतकर्ता का पक्ष सशस्त्र हमलावर था।[पैरा 35 और 36] [807-ई-एफ, एच; 808-ए]

1.10 ए-1 और ए-3 के रिवॉल्वरों पर गोलियों के साक्ष्य का अभाव में और वर्तमान अपीलार्थियों के खिलाफ पीडब्लू 3,6,13 और 18 के बयान को ध्यान में रखते हुए, मामले को एक स्वतंत्र लड़ाई के भीतर लाने के लिए, दोनों पक्षों को सशस्त्र और युद्ध आदेशने के लिए तैयार रहना होगा, वर्तमान मामले में लागू किया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक अभियुक्त अपने अकेले व्यक्तिगत कार्य के लिए उत्तरदायी होगा।[पैरा 37] [808-□ □ ]

1.11 इस प्रकार ए-1 और ए-3 को, उनके व्यक्तिगत कृत्यों पर ध्यान दें हुए, केवल यू/एस के तहत दोषी ठहराया जा सकता है।324 भा.दं.सं.. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ए-1 और ए-3 ने क्रमशः लगभग 11 और 10 महीने बिताए हैं, वही पर्याप्त होगा और आगे किसी कारावास की आवश्यकता नहीं है, इसलिए, दोनों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि उनकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है।[पैरा 40] [809-एफ-जी]

2. यह सही है कि क्रॉस-केस में साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, न तो निचली अदालत और न ही उच्च निचली अदालत ने क्रॉस-केस में दिए गए साक्ष्य पर भरोसा किया, लेकिन उन पर अलग से मुकदमा चलाया गया और वास्तव में क्रॉस मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ उच्च निचली अदालत में अपील अभी भी लंबित हैं।[पैरा 28] [804-जी; 805-बी]

मिट्टूलाल और अन्न. वी.मध्य प्रदेश राज्य (1975) 3 धारा 529 संदर्भित किया गया।

3. यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को फिर से नहीं खोलेगा जब तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष होते हैं और इसमें शामिल कानून का कोई सवाल नहीं होता है और निष्कर्ष विकृत नहीं होता है। संविधान का अनुच्छेद 136 किसी पक्ष को अपील करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। यह केवल इस न्यायाधीशालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है कि वह उपयुक्त मामलों में हस्तक्षेप करने वालों को कम से कम प्रयोग करे जहां साक्ष्य को पढ़ने में अवैधता या गलतफहमी या गलती के परिणामस्वरूप न्यायाधीश का गंभीर दुरुपयोग हुआ है या भौतिक साक्ष्य को अनदेखा करने, हटाने या अवैध रूप से स्वीकार करने से हुआ है। [पैरा 29) [805-सी-ई]

शंभू दास उपनाम बिजॉय दास और अन्न बनाम असम राज्य (201 ओ) 10 धारा 37 4:201 ओ (11) एस. सी. आर. 493-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ:

(1978) 4 धारा 394 पैरा 202011 (6) एस. सी. आर. 1072 पैरा 22 जी2011 (10) एस. सी. आर. 739 पैरा 242006 (4) सप्लीमेंट पर निर्भर था। एस. सी. आर. 636 पैरा 262004 (6) सप्लीमेंट पर निर्भर था। एस. सी. आर. 633 पैरा 26 784 सर्वोच्च अधिकार क्षेत्र रिपोर्ट [2012] 13 एस. सी. आर. (1975) 3 धारा 529 पैरा 282010 (11) एस. सी. आर. 493 पैरा 29

अपराधिक अपीलीय क्षेत्रधिकार आपराधिक अपील सं 634/2012

2011 के डी. बी. दाण्डिक अपीलीय सं 189 में जयपुर में राजस्थान पीठ के लिए उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

के साथ

आपराधिक अपील सं 635/2012

उदय यू. ललित, के. टी. एस. तुलसी, मुकुल गुप्ता, जसबिर सिंह मलिक, एम. जी., नितिन सांगरा, गौरव अग्रवाल, रविंदर सिंह आदिल सिंह बोपाराए, एम. खान, रवींद्र एस. गरिया, राहुल वर्मा, प्रगति नीखरा वरुण पुनिया, इरशाद अहमद, रंजना नारायण, बी. के. प्रसाद उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय पी. सतशिवम, जे. द्वारा दिया गया था

1. ये अपीलें राजस्थान के लिए उच्च न्यायालय, जयपुर की पीठ द्वारा डी. बी. दाण्डिक अपीलीय संख्या 2011 की 189 और 188 में पारित सामान्य निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई हैं, जिसमें उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया और 2001 के सत्र मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) संख्या 1, अजमेर के न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के फैसले की पुष्टि की।

2. संक्षिप्त तथ्य

(क) यह मामला खादिम मोहल्ला, झालरा, अजमेर के दो समूहों के बीच लड़ाई से संबंधित है, जिसमें एक इदरीस की मौत हो गई और 1992 की 90 और 91 की 2 प्राथमिकियां दर्ज की गईं।

(बी) 14.04.1992 पर, पुरानी प्रतिद्वंद्विता के कारण एक शब्बीर के घर पर एक समारोह के दौरान खलील चिश्ती (ए-2) और असलम चिश्ती (1992 की प्राथमिकी संख्या 90 में शिकायतकर्ता) के चचेरे भाई खुर्शीद पहलवान के बीच बहस हुई। उसी शाम, खुर्शीद ने शब्बीर के चचेरे भाई इदरीस को दोनों पक्षों के बीच समझौते के माध्यम से मामले को हल करने के लिए बुलाया था। उसी के अनुसरण में, इदरीस, शमीम, असलम, मुस्तकीम, आसिफ, सगीर और जावेद (रिश्तेदार) खलील चिश्ती के घर की ओर बढ़े जहाँ उन्हें खलील चिश्ती (ए-2), यासिर चिश्ती (ए-1), अकील चिश्ती

(ए-3) और फारुख चिश्ती (ए-4) मिले जो पहले से ही वहाँ मौजूद थे। घर में प्रवेश करने पर, उन्हें एहसास हुआ कि खलील (ए-2) के हाथ में तलवार थी और फारुख (ए-4) के हाथ में बंदूक थी, जबकि यासिर और अकील के पास रिवॉल्वर थी और आरोपी दल ने तुरंत पीछे से दरवाजा बंद कर दिया और खलील चिश्ती (ए-4) ने दरवाजा बंद कर दिया।<sup>2)</sup> चिल्लाया, "किसी को भागना नहीं चाहिए, उन सभी को मार डालो।" उनकी मंशा देख आदेश, शिकायत आदेशता पक्ष ने उनकी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, जिस समय फारुख (ए-4) ने इदरीस पर गोली चलाई, जिसके परिणामस्वरूप उनकी दाहिनी आंख में चोट लग गई। खलील (ए-2) ने शिकायतकर्ता-असलम चिश्ती को तलवार भी मारी जो उसके माथे पर लगी और यासिर और अकील ने भी गोलियां चलाईं। बाद में, यह देखते हुए कि घायलों को गोली मार दी गई है, आरोपी लोग भाग गए। इसके बाद, खुर्शीद और शमीम असलम चिश्ती और इदरीस को अस्पताल ले गए जहां इदरीस ने दम तोड़ दिया।

(ग) उसी दिन, यानी आईडी<sup>1</sup> पर, असलम चिश्ती ने यासिर (ए-1), खलील (ए-2), अकील (ए-3) और फारुख (ए-4) के खिलाफ पुलिस स्टेशन गंज, अजमेर में 1992 की 90 नंबर की प्राथमिकी दर्ज की।

(घ) उसी दिन लगभग 10 बजे:30 11 तक:00 इलाज के दौरान अकील चिश्ती द्वारा दिए गए बयान पर पी. एस. गंज, अजमेर में 1992 की 91 नंबर की एक और प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि लगभग 5 बजे:00 5 तक:30 दोपहर में, जब वह अन्य लोगों के साथ अपने घर में बैठे थे, तो उन्होंने अचानक घर की गिरल पर पथराव होते देखा। जब वे सभी मामले को समझने के लिए छत पर गए, तो उन्होंने इदरीस, शमीम, असलम, मुस्तकीम, आसिफ, सगीर और जावेद को हथियारों से लैस वहां खड़ा पाया। उसी के बारे में पूछने पर, इदरीस ने फारुख (ए-4) पर चाकू से वार किया और शमीम ने अकील (ए-3) पर गोली चला दी जो लक्ष्य से चूक गया। इस बीच, अकील (ए-3) अपने पिता की एक राइफल लेकर आया लेकिन सगीर, आसिफ

और जावेद ने उससे वह छीन ली और असलम ने उसे पीछे से उसकी कमर में चाकू मार दिया जिससे वह गिर गया। आसिफ ने उस पर भी गोलियां चलाईं जो इदरीस को लगीं। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई।

(जांच के बाद, 4 व्यक्तियों, यासिर, खलील, अकील और फारुख के खिलाफ 1992 की प्राथमिकी आर. संख्या 90 में और 6 व्यक्तियों, शमीम, असलम, मुस्तकीम, आसिफ, सगीर और जावेद के खिलाफ 1992 की क्रॉस प्राथमिकी आर. संख्या 91 में आरोप पत्र दायर किए गए और दोनों मामले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) संख्या 1, अजमेर की अदालत में दर्ज किए गए और सत्र मामला संख्या 157/2001 (प्राथमिकी आर 90/1992) और सत्र मामला संख्या 178/2001 (प्राथमिकी आर 91/1992) के रूप में दर्ज किए गए।

(च) निचली अदालत ने 2001 के सत्र मामला संख्या 157 में दिनांक 1 के फैसले से फारुख चिश्ती (ए-डी 4), यासिर चिश्ती (ए-1) और अकील चिश्ती (ए-3) को भारतीय दंड संहिता 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की खंड 34 के साथ पठित खंड 302 और 324 के तहत दोषी ठहराया, जबकि खलील चिश्ती (ए-2) को आई. पी. सी. की खंड 302 और 324 के तहत दोषी ठहराया गया था। ए-1, ए-2, ए-3 और ए-4 को रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 20, 000/-, चूक में, आई. पी. सी. की खंड 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 6 महीने की अवधि के लिए आर. आई. से गुजरना होगा। उन सभी को 2 साल के लिए साधारण कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। 2, 000/-, चूक में, आई. पी. सी. की खंड 34 के साथ पठित खंड 324 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 1 महीने के लिए साधारण कारावास को आगे बढ़ाने के लिए।

(छ) उसी दिन, विचारण न्यायालय ने 2001 के सत्र मामला संख्या 178 में अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराया और उन सभी को 10 साल के लिए आर. आई. के

साथ-साथ ₹10,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई। चूक में, भा.दं.सं. सी. की खंड 149 के साथ पठित खंड 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 6 महीने के लिए आर. आई. से गुजरना होगा। उन्हें भा.दं.सं. सी. की खंड 148 के तहत आर. आई. को 2 साल, आर. आई. को 1,000/- रुपये के जुर्माने के साथ 3 साल की सजा सुनाई गई, चूक में, भा.दं.सं. सी. की खंड 452 के तहत एक महीने के लिए आर. आई. और भा.दं.सं. सी. की खंड 149 के साथ पठित खंड 324 के तहत 2 साल के लिए आर. आई. से गुजरना पड़ा। उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए, 1992 की प्राथमिकी आर. 91 में नामित सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2011 दाण्डिक अपीलीय सं 131 दायर की जो अभी भी लंबित है।(ज) सत्र मामला सं. 157/2001 में फैसले को चुनौती देते हुए, यासिर चिश्ती और अकील चिश्ती ने डी. बी. दाण्डिक अपीलीय सं 188/2011 दायर की, डॉ. मोहम्मद खलील चिश्ती ने 2011 की डी. बी. दाण्डिक अपीलीय सं 189 दायर की और फारुख चिश्ती ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2011 की डी. बी. दाण्डिक अपीलीय सं 423 दायर की। दिनांक 20.12.2011 के एक सामान्य निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने सभी अपीलों को खारिज कर दिया और निचली अदालत द्वारा पारित फैसले की पुष्टि की।

(II) उक्त निर्णय से व्यथित होकर, डॉ. मोहम्मद खलील चिश्ती ने 2012 दाण्डिक अपीलीय सं 634 को प्राथमिकता दी और यासिर चिश्ती और अकील चिश्ती ने इस न्यायालय के समक्ष 2012 दाण्डिक अपीलीय सं 635 को प्राथमिकता दी। 3) श्री उदय यू. ललित, 2012 दाण्डिक अपीलीय सं 634 में डॉ. मोहम्मद खलील चिश्ती के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील, श्री के. टी. एस. तुलसी, 2012 दाण्डिक अपीलीय सं 635 में अपीलकर्ता यासिर चिश्ती और अकील चिश्ती के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील, श्री राहुल वर्मा, विद्वान वकील और जसबिर सिंह मलिक, दोनों अपीलों में राज्य के लिए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता और श्री मुकुल गुप्ता, आपराधिक अपील संख्या 634/2012 भारत संघ के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वकील।

तर्क:

4. 1992 की एफ. आई. आर. सं. 90 और 1992 की क्रास एफ. आई. आर. सं. 91 दिनांक आई. डी. 1 द्वारा से हमें लेने के बाद, अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा पूरी सामग्री, 2001 के सत्र मामले सं. 157 और 2001 के सत्र मामले सं. 178 में निचली अदालत के फैसले और उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के तर्क पर भरोसा आदेशने के बाद, श्री ललित के साथ-साथ श्री के. टी. एस. तुलसी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तर्क दिया कि शिकायतआदेशता पक्ष के सदस्य आक्रामक थे, उन्होंने विभिन्न हथियारों से लैस एक गैरकानूनी सभा का गठन किया और अपने सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए अभियुक्त व्यक्तियों को पीटने के लिए अपने परिसर की छत पर चढ़ गए। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थियों/अभियुक्त व्यक्तियों ने कोई अपराध नहीं किया था और उन्होंने जो कुछ भी किया वह उनके निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग था। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अभियुक्त व्यक्तियों का मृतक-इदरीस की हत्या करने का कोई सामान्य उद्देश्य था। उन्होंने आगे कहा कि निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा कि इदरीस, असलम, आसिफ, शमीम, मुस्तकीम, सगीर और जावेद सहित शिकायतकर्ता पक्ष विधिवत सशस्त्र थे और आरोपी व्यक्तियों के स्थान पर आए थे। ऐसी परिस्थितियों में, अभियुक्त अपीलार्थी अपने व्यक्ति पर निजी बचाव के अधिकार का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि फारुख (ए-4) और अकील (ए-3) को कैसे चोटें आईं। उन्होंने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष ने घटना की वास्तविक उत्पत्ति को दबा दिया।

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय का निर्णय साक्ष्य पर और कानून के तय किए गए सिद्धांतों के आलोक में आधारित है। यह बताया गया है कि अभियुक्त अपीलकर्ताओं ने पूरी तैयारी के बाद खुर्शीद, शमीम, इदरीस और शिकायतकर्ता पक्ष के अन्य सदस्यों को उनके घर पर

मिलने का संदेश भेजा। यह बताया गया है कि जैसे ही शिकायतकर्ता पक्ष के सदस्यों ने अपने घर की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया और छत की ओर बढ़े, आरोपी अपीलकर्ताओं ने उनका पीछा किया और विभिन्न हथियारों का उपयोग करके उन्हें घायल कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप, इदरीस और असलम गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में इदरीस ने दम तोड़ दिया। अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है और विवादित निर्णय किसी भी दुर्बलता या अवैधता से ग्रस्त नहीं है। 6. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और सभी प्रासंगिक सामग्रियों का अध्ययन किया है।

चर्चा:

7. यह विवाद में नहीं है कि उसी घटना के संबंध में जो 14.04.1992 पर हुई थी, दो प्राथमिकियां थीं, अर्थात् 1992 की प्राथमिकी आर. संख्या 90 और क्रॉस प्राथमिकी आर. संख्या 91:1992 से। इन अपीलों में, हम 1992 की प्राथमिकी आर. संख्या 90 के बारे में चिंतित हैं जिसमें वर्तमान अपीलार्थियों और एक फारुख को आरोपी के रूप में फंसाया गया था। उक्त प्राथमिकी आर. सैयद श्री असलम द्वारा की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिनसे पीडब्लू-3 के रूप में पूछताछ की गई थी। वह मियां हाउस, खादिम मोहल्ला, अजमेर का निवासी है। आदेश में कहा गया है कि शब्बीर के स्थान पर 'पीला की रसम' के अवसर पर खलील चिश्ती (ए-2) और खुर्शीद पहलवान के बीच पुरानी प्रतिद्वंद्विता के कारण बहस हुई थी, जिसके बाद खुर्शीद ने शाम को अपने भाई इदरीस को बुलाया था ताकि आखिरकार समझौते के माध्यम से मामले को सुलझा लिया जा सके। जब इदरीस, शमीम-उसका रिश्तेदार और मोहम्मद। असलम चिश्ती-शिकायतकर्ता उस समय खुर्शीद के घर गया, एक तारिक मोहम्मद ने उन्हें बताया कि खलील चिश्ती उन्हें समझौते के लिए बुला रहा है, जिसके बाद, वे सभी, अर्थात्, इदरीस, शमीम, मोहम्मद। असलम, खुर्शीद, उनके भाई सगीर खलील के

घर गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने पाया कि खलील, फारुख, यासिर और अकील घर पर मौजूद थे। यह आगे कहा गया है कि घर में प्रवेश करने के बाद आरोपी पक्ष ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया और खलील चिल्लाया कि "वे शौ!न भागें, उन सभी को मार दें। यह आगे कहा गया है कि खलील के पास तलवार थी और फारुख के पास राइफल थी। जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो उस समय फारुख (ए-4) ने इदरीस (मृतक) पर गोली चला दी जो उसकी दाहिनी आंख में लग गई और वह नीचे गिर गया। खलील (ए-2) ने मोहम्मद के सिर पर तलवार से वार किया। असलम चिश्ती-शिकायतकर्ता जो उसके माथे पर मारा गया और उसके मंदिर और आंख पर मारा गया। रिवाँल्वर से लैस अकील (ए-3) और यासिर (ए-1) ने भी गोलीबारी शुरू कर दी। सभी आरोपी भाग गए और खुर्शीद और शमीम इदरीस को अस्पताल ले गए जहां उसने दम तोड़ दिया। उपरोक्त कथन शाम 5:45 बजे 14.04.1992 पर दर्ज किया गया था।

8. यद्यपि हम याचिका और वर्तमान अपीलार्थियों के बचाव को ध्यान में रखते हुए 1992 की क्रॉस एफ. आई. आर. संख्या 91 दिनांक 1 के बारे में सीधे तौर पर चिंतित नहीं हैं, लेकिन उसी की सामग्री को ध्यान दें प्राथमिकीना वांछनीय है। इस क्रॉस एफ. आई. आर. में शिकायतप्राथमिकीता वर्तमान अपील में अपीलकर्ता अकील चिश्ती (ए-3) है। निम्नलिखित व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में दिखाया गया था, अर्थात्, इदरीस, शमीम, असलम, मुस्तकीम, आसिफ, सगीर और जावेद। शिकायतकर्ता के अनुसार, बैतूल, झालरा, दरगाह शरीफ, अजमेर के निवासी अकील चिश्ती ने बताया कि आईडी1 पर शाम 5 से 5:30 बजे जब वह फारुख चिश्ती के कमरे में थे, तो उन्होंने अचानक अपने घर की गिरल पर पथराव होते देखा। जब वे छत पर गए तो उन्होंने पाया कि इदरीस, उसका भाई शमीम, असलम, मुस्तकीम, आसिफ, सगीर और जावेद हथियारों से लैस थे और शमीम के पास देसी पिस्तौल थी। जब फारूक से पथराव के बारे में पूछा गया तो इदरीस ने उस पर चाकू से वार कर दिया। शमीम ने उस पर गोली चला दी जिससे वह चूक गया। यह आगे कहा गया है कि शिकायतकर्ता अकील अपने

पिता की 12 बोर की लाइसेंस प्राप्त राइफल लेकर आया था, लेकिन सगीर, आसिफ और जावेद ने उससे वह छीन ली और असलम ने पीछे से उसकी कमर में चाकू के घाव किए और वह नीचे गिर गया। आसिफ ने अपनी राइफल से गोली चला दी जो उसे छूट गई और मोहम्मद को लगी। पड़ोस में कई लोग जमा हो गए थे जिन्होंने "मार दिया मार दिया" का नारा लगाया था। इन लोगों ने उनके घर में घुसकर उन पर हमला किया। उपरोक्त बयान अजमेर के एस. एच. ओ. पुलिस स्टेशन द्वारा दोपहर 10.30 पर दर्ज किया गया था।

9. यह ध्यान दें योग्य है कि 1992 की प्राथमिकी संख्या 90 के संबंध में, वर्तमान अपीलकर्ताओं और एक फारुख को निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी। यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि 1992 की क्रॉस प्राथमिकी आर. संख्या 91 के संबंध में, उसी दिन उसी विचारण न्यायाधीश ने उन सभी को विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया और सजा सुनाई और उन दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है।

10. अब, आइए हम अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा भरोसा किए गए गवाहों और सामग्रियों पर विचार करें।

असलम चिश्ती (पीडब्लू-3):

11. अपने साक्ष्य में, उन्होंने अपदस्थ किया कि मृतक इदरीस उनका चचेरा भाई था और खुर्शीद और साहिर भी उनके चचेरे भाई थे। शमीम उसका असली छोटा भाई है। उसने अदालत में एक पाकिस्तानी नागरिक खलील चिश्ती (ए-2) की पहचान की। वह आरोपी फारुख, यासिर और अकील से परिचित था। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने पिता से पता चला कि खलील चिश्ती (ए-2) और खुर्शीद पहलवान के बीच शब्बीर के स्थान पर "पीला की रसम" के अवसर पर पुरानी प्रतिद्वंद्विता के कारण कुछ झगड़ा हुआ था।

उन्होंने आगे बताया कि आईडी1 की शाम को जब वह अपने भाइयों शमीम और इदरीस के साथ अपने घर पर थे, तो खुर्शीद का बेटा उनके घर आया और बताया कि उनके पिता उन सभी को फोन कर रहे हैं। वहाँ पहुँचने के बाद, खुर्शीद ने उन्हें मामले को हल करने के लिए कहा। इस बीच, तारिक मोहम्मद नामक व्यक्ति ने उन्हें सूचित किया कि खलील चिश्ती (ए-2) ने उन्हें बैठक के लिए बुलाया है। वह अन्य लोगों के साथ खुर्शीद के आवास पर गए। वहाँ से वह मृतक-इदरीस, शमीम, खुर्शीद, सगीर, जावेद, मुस्तकीम और आसिफ के साथ खलील के घर की ओर बढ़ा और वहाँ पहुँचने पर उन्होंने देखा कि खलील प्रवेश द्वार पर खड़ा था। खलील के घर में घुसते ही वहाँ मौजूद अन्य लोगों ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया और खलील उन सभी को मारने के लिए चिल्लाया। अपनी जान बचाने के आदेश वह इदरीस, शमीम, आसिफ और अन्य लोगों के साथ बैतूल मंजिल पर चढ़ गया और कप्तान हाउस की छत पर पहुँच गया। उस समय आरोपी खलील, फारुख, यासिर और अकील उस स्थान पर आए और खलील के पास नंगी तलवार थी और फारुख के पास राइफल थी, यासिर और अकील के पास राइफल थी। फारुख ने लक्ष्य तय किया और अपने भाई इदरीस को गोली मार दी। गोली इदरीस की दाहिनी आंख में लगी थी जिससे वह वहीं गिर गया था। खलील की खोपड़ी और माथे पर तलवार के दो घाव थे। अकील और यासिर ने भी अपनी-अपनी रिवॉल्वर से गोलियाँ चलाई थीं, लेकिन वे भागने में सफल रहे। उन्होंने स्वीकार किया कि अकील और यासिर की रिवॉल्वर से लगी आग किसी को नहीं लगी थी। उपरोक्त कथन के दौरान, पीडब्लू-3 ने स्वीकार किया कि दो पुलिस कर्मी उस पहुँचे थे। छत पर, विशेष रूप से, जब अकील और यासिर गोलीबारी कर रहे थे। पीडब्लू-3 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि हालांकि उन्होंने वर्तमान अपीलार्थियों की संलिप्तता के साथ-साथ फारुख की भूमिका के बारे में अभियोजन पक्ष के मामले को सुनाया, लेकिन उन्होंने दो पुलिस कर्मियों के आगमन को स्वीकार किया, अर्थात्, भंवर सिंह (पीडब्लू-4) और भंवरलाल शर्मा (पीडब्लू-5) छत पर थे जब अकील और यासिर गोलीबारी कर रहे थे।

भंवर सिंह (पीडब्लू-4):

12. संबंधित समय में, पीडब्लू-4 को पुलिस पोस्ट त्रिपोलिया गेट, पुलिस स्टेशन गंज, अजमेर में एलएचसी के रूप में तैनात किया गया था। अपने साक्ष्य में उन्होंने कहा है कि आईडी1 पर शाम करीब साढ़े चार बजे उन्हें वायरलेस नियंत्रण कक्ष से जानकारी मिली कि झालरा में झगड़ा हो गया है। उक्त सूचना मिलने पर पीडब्लू-4 और भंवर लाल शर्मा (पीडब्लू-5) मौके पर पहुंचे और अहमद चिश्ती के घर गए। पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि सुबह बच्चों के मुद्दे पर कुछ झगड़ा हुआ था। नियंत्रण कक्ष को फोन करने लिए, वे दोनों नियंत्रण कक्ष में स्थित कमरे में गए। एक अहमद चिश्ती के घर की पहली मंजिल और जब वे लौट रहे थे, तो उन्होंने पाया कि तलवार और हॉकी स्टिक से लैस 5-6 लोग जमीन से ऊपर चढ़ गए थे। उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वे नहीं रुके। उनमें से वह शमीम, असलम और इदरीस को जानता था। उन्होंने आगे कहा कि वे "फारुख को बाहर लाओ", "पाकिस्तानी (ए-2) को बाहर लाओ और वह जहां है, हम उसे मार देंगे" के नारे लगा रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके हस्तक्षेप के बावजूद हमलावर उस घर की दूसरी मंजिल की छत पर पहुंच गए। पीडब्लू 4 और 5 दोनों ने उनका अनुसरण किया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने फारुख चिश्ती (ए-4) को अपने साथ 12 बोर की बंदूक के साथ देखा था। खलील (ए-2), यासिर और अकील के पास तलवारें थीं। फारुख छत पर गया और अपनी बंदूक से गोली चलाई और गोली इदरीस की दाहिनी आंख में लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब पीडब्लू-5 बीच में आया तो उसे भी चोटें आईं। वह उसी स्थान पर दोपहर 1 बजे तक रहे और दोपहर 1 बजे के बाद वह त्रिपोलिया गेट गए, पी. एस. ने अपनी दैनिक डायरी में अपनी लिखावट में आवश्यक प्रविष्टियां कीं जो एक्स. एच. है। पी-3। उन्होंने कांस्टेबल भंवर लाल शर्मा (पीडब्लू-5) को घटना स्थल पर छोड़ दिया।

13. चूंकि पीडब्लू-4 ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की खंड 161 के तहत दिए गए उनके बयान का खंडन किया, इसलिए लोक अभियोजक ने उनसे

जिरह करने की अनुमति मांगी।जिरह में भी, उसने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को बयान दिया था और घटना के समय, मृतक-इदरीस और अन्य तलवारों और हॉकी स्टिक से लैस थे और वे ऊपर जा रहे थे जो एक्सएच है। पी-4 हालांकि पीडब्लू-4 शत्रुतापूर्ण हो गया, कुछ हद तक, वह एक पुलिस कांस्टेबल होने के नाते, सूचना मिलने पर और उसे डायरी में दर्ज करने के बाद वह एक अन्य पुलिस कांस्टेबल भंवर लाल शर्मा (पीडब्लू-5) के साथ पुलिस स्टेशन से मौके पर चला गया और देखा कि शिकायतकर्ता पक्ष तलवार और हॉकी स्टिक लेकर छत की ओर भागे।यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान अभियुक्त अपीलार्थी खलील चिश्ती के घर के अंदर थे और शिकायतकर्ता का समूह हथियारों के साथ वहां पहुंचा था।यह भी स्पष्ट किया गया है कि उनके साथ एक अन्य कांस्टेबल पीडब्लू-5 भी था और घटना को देखने के बाद, वह त्रिपोली पहुंचा और पीडब्लू-5 को मौके पर छोड़कर आवश्यक प्रविष्टियां कीं।जैसा कि अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ठीक ही बताया है, संबंधित स्थान और समय पर पीडब्लू 4 और 5 की उपस्थिति पर विवाद नहीं किया जा सकता है। पीडब्लू-4 के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता पक्ष तलवार और हॉकी स्टिक के साथ मौके पर पहुंचे थे।हथियारों के साथ शिकायतप्राथमिकीताओं की उपस्थिति 1992 की क्रॉस एफ. आई. आर. संख्या 91 का विषय है।

भंवर लाल शर्मा सीपीडब्ल्यू-51:

14. प्रासंगिक समय में, वह त्रिपोलिया गेट के पुलिस स्टेशन में एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में तैनात थे और 14.04.1992 पर ड्यूटी पर थे।उनके अनुसार, उस दिन शाम करीब साढ़े चार बजे उन्हें और एक अन्य कांस्टेबल पीडब्लू-4 को त्रिपोलिया पी. एस. में पुलिस नियंत्रण कक्ष से वायरलेस पर सूचना मिली कि झालरा में कुछ लड़ाई चल रही है। ऐसी जानकारी सुनकर वे दोनों झालरा गए और देखा कि ऐसा कोई झगडा नहीं है। नियंत्रण कक्ष को इसकी सूचना देने के लिए वे सीढियों का उपयोग आदेशके अहमद चिश्ती के घर गए। उसी समय, उसने देखा कि शमीम (क्रॉस एफ.

आई. आर. में ए-6) अपने हाथ में हॉकी की छड़ी के साथ ऊपर की ओर भाग रहा था, असलम (क्रॉस ए. आई. आर. में ए-1) तलवार से लैस था और दो और लोग जो हथियारों से लैस थे, ऊपर की ओर जा रहे थे।दोनों (पीडब्लू-4 और (पीडब्लू -5) उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वे नहीं रुके।वे दोनों चिश्ती मंजिल के कमरे में गए और छत पर उन्होंने देखा कि शमीम चिश्ती और अन्य लोग फारुख और अन्य लोगों को गाली दे रहे थे और फिर वे जमील चिश्ती के कमरे में गए और पथराव करना शुरू कर दिया।स्थिति की गंभीरता को देखकर और अप्रिय घटना से बचने के लिए, पीडब्लू-5 अन्य पुलिस कर्मचारियों को बुलाने के लिए नीचे चला गया, जबकि पीडब्लू-4 छत पर ही रहा।उन्होंने गोली चलने की आवाज भी सुनी।जब वह फोन कर वापस आया तो उसने देखा कि इदरीस कसान कमरे में लेटा हुआ था और शारीरिक रूप से विकसित था।:घायल हो गए। जिस स्थान पर इदरीस लेटा हुआ था, उस स्थान से 12 बोर की बंदूक भी मिली थी। उन्होंने यह भी बताया कि उनके संदेश के आधार पर अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने शमीम और अन्य लोगों को सीढ़ियों पर रोकने की कोशिश करते समय उन्हें लगी चोटों का भी उल्लेख किया। उन्होंने आगे बताया कि आधी रात को, लगभग 12.50 सुबह, वे त्रिपोलिया गेट पी. एस. आए और अपने आगमन के समय की आवश्यक प्रविष्टियाँ कीं जो कि एक्स. एच. है। पी-3.चूंकि उन्होंने संहिता की खंड 161 के तहत अपने बयान का खंडन किया, इसलिए लोक अभियोजक ने उनसे जिरह आदेशने के लिए अदालत से अनुमति मांगी।जिरह में भी उन्होंने जोर देकर कहा कि घटना के समय केवल शमीम (क्रॉस एफ. आई. आर. में ए 6) ही जमील चिश्ती के घर में पूरी ताकत से नीचे पत्थर फेंक रहा था।उन्होंने असलम और शमीम के खिलाफ लड़ाई और एफ. आई. आर. दर्ज होने का भी उल्लेख किया।

15. पीडब्लू-4 की तरह, पीडब्लू-5 ने वायरलेस संदेश की प्राप्ति से लेकर जमील चिश्ती के घर पर हुई झड़प तक की घटना का वर्णन किया।यह इंगित करना प्रासंगिक है कि पीडब्लू 4 और 5 किसी भी समूह से जुड़े नहीं थे, दूसरी ओर, वे त्रिपोली पी.

एस. के पुलिसकर्मी थे जिनका क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र था। संबंधित रजिस्ट्रारों में उनके जाने और पुलिस स्टेशन पहुंचने की प्रविष्टियां भी उनके बयान को साबित करती हैं। उनके बयान के आलोक में, हमने उनके साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है और यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता का पक्ष तलवार, हॉकी स्टिक जैसे हथियारों के साथ मौके पर आया था और उस समूह के कुछ लोगों ने पथराव भी किया था। ये पहलू, हालांकि निचली अदालत और उच्च न्यायालय विश्वास देने में विफल रहे, अपीलकर्ता यह दावा करने में उचित हैं कि शिकायतकर्ता समूह घटना और उन्हें हुई चोटों के लिए जिम्मेदार था। पीडब्लू 6,13 और 18 का प्रमाण:

16. राज्य के वकील के कहने पर, हमें पीडब्लू 6,13 और 18 के साक्ष्य द्वारा से लिया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने अभियोजन पक्ष के रुख का समर्थन किया और दावा किया कि यह अपीलकर्ता थे जो चोटों का कारण बने और विशेष रूप से, इदरीस की मृत्यु फारुख द्वारा अपनी रिवॉल्वर का उपयोग करके चलाई गई गोली के कारण हुई। उन्होंने यह भी कहा कि खलील चिश्ती (ए-2) द्वारा इस्तेमाल की गई तलवार के कारण उन्हें चोटें आईं। यह भी उनका दावा है कि अन्य दो आरोपी यासिर चिश्ती और अकील चिश्ती, ए-1 और ए-3 ने रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया था, लेकिन उनकी गोलियां किसी को नहीं लगी थीं। जैसे पीडब्लू 6,13 और 8

18, पीडब्लू-3, जिसे ए2 के कहने पर तलवार से चोट लगी थी, ने भी अभियोजन मामले के बारे में बताया। पीडब्लू-3 के साक्ष्य से यह भी देखा जाता है कि फारुख (ए-4) को भी चोटें आईं, जिसके लिए अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पीडब्लू 3,613 और 18 के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, भले ही हम अभियोजन पक्ष के मामले को प्रतिग्रहण करना करते हैं, अभियोजन पक्ष की ओर से जांचे गए आधिकारिक गवाहों, अर्थात् पीडब्लू 4 और 5 के बयान से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि शिकायतकर्ता तलवार और हॉकी स्टिक लेकर चिश्ती के घर की ओर भाग रहे थे और पथराव भी कर रहे थे। इन परिस्थितियों में, जैसा कि अपीलार्थियों के

वकील द्वारा सही बताया गया है, शिकायतकर्ता जो क्रॉस मामले में आरोपी थे, वे भी अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए जिम्मेदार थे।

ए 2 के निवास पर घटना:

17. अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों, अर्थात् पीडब्लू 3,4,5,6 13 और 18 ने गवाही दी कि घटना ए-2, अर्थात् चिश्ती मंजिल के आवास पर हुई थी। यह दो पुलिस कांस्टेबलों के स्पष्ट बयान से भी स्पष्ट है। पीडब्लू 4 और 5 ने कहा कि एक फोन कॉल मिलने पर, वे त्रिपोली पुलिस थाना से निकले और चिश्ती मंजिल से सटे कप्तान के घर पहुंचे। यह स्पष्ट है कि यह अपीलकर्ता/आरोपी नहीं थे जो हथियारों के साथ अपने घर से बाहर गए थे, लेकिन अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुसार भी, घटना ए-2 के आवास पर हुई थी। यह भी स्पष्ट है कि वे सभी तलवार और हॉकी स्टिक जैसे हथियारों के साथ उक्त घर में घुसे थे जिन्हें हम अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए सबूतों से पहले ही नोट कर चुके हैं।

इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि फारुख (ए-4) और अलदी (ए 3 एल) को कैसे चोट लगी:

18. अभियोजन दस्तावेज, अर्थात्, फारुख की चोट रिपोर्ट दिनांक 14.04.1992 और अकील की चोट रिपोर्ट दिनांक 14.04.1992 को संलग्नक पी-5 (कोली) के रूप में रखा गया है। मेडिकल ज्यूरिस्ट विभाग, जे. एल. एन. मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अजमेररेड्स द्वारा जारी की गई फारुख चिश्ती (ए-4) से संबंधित चोट की रिपोर्ट इस प्रकार है:

"एम. एस. डब्ल्यू. III, समय-शाम 5:45 बजे में भर्ती किया गया- 14.4.1992, 839/92 चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर चोट रिपोर्ट प्रपत्र पुलिस के साथ श्री फारुख चिश्ती पुत्र श्री सादिक चिश्ती की चोट की रिपोर्ट, आयु 26 वर्ष, जाति-मुस्लिम, खादिम मोहल्ला, अजमेर के निवासी, पुलिस रिपोर्ट संख्या

दिनांकित। संलग्न। चोट का प्रकृति आकार सामान्य जो पहचान एक्स-रे विशेष चोट या कटाव के विवरण के निशान के प्रकार, चोट जो गंभीर हथियार ने ताजबीज-शरनी के घाव को घायल कर दिया, आंशिक रूप से चोट आदि के इंचों को कुचलने का कारण बना। लंबाई, शरीर की चौड़ाई और गहराई 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टेब घाव 4 0.5 से. मी. □ गहराई नाभि क्षेत्र पर तेज एम. एफ. 1% □% फ्रेशिन, दाएँ से. मी. पुराना निशान नाभि के तिरछे लाफ्ट साइड के आर. एल. जी. 1 पीस पैर ऊपरी थर्ड 2। मध्य एक्सलियर लिनो में चेक वाली 6 सेमी बेलोवी 1 ऑक्सिला के लॉफ्ट एलक्ट्राल साइड पर 4 3/4 सेमी □ दबाएँ। 3. स्टेब घाव 3 1 1? आघात की स्थिति में घायल बाएं केशिका क्षेत्र पर, आई आई ओपिनियन

इसगर्लक्ल नोटएसडी/- डॉ के बाद। वी. डी. काविया, एम. डी. रीडर, चिकित्सा विभाग के प्रमुख. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, अजमेर डॉ. मोहम्मद खलील चिश्ती बनाम राज्य ओ. एफ. राजस्थान [पी. साथशिवम, जे.] फारुख चिश्ती के ऑपरेटिव नोट्स इस प्रकार हैं: ऑपरेटिव नोट्स रोगी का नाम फारुख चिश्ती नहीं। 9741797 14/4/92 सर्जिकल पैथोलॉजी-स्टैब घाव 1। पेट 2. लेफ्टिनेंट चेस्ट 3. बैक एनेस्थीसिया-□ □ □ □ □ □ □ □ -एक्सप्लेनेटरी हैप्रोटोमी और टियर इंस्टोमाच की मरम्मत। चीरा-छुरा घोंपने के घाव की निरंतरता (आर. टी. पैरामेडियन)-एक खोज में यह पाया गया कि सेरोसा के पूर्वकाल पेट की दीवार में एक आँसू था। वाहिका से खून बह रहा था जिसे बांध दिया गया था और आँसू बह गए थे और परतों में बंद कर दिया गया था। □ छाती (लेफ्टिनेंट साइड और पीठ) पर घाव मांसपेशियों के गहरे थे और एक परत में सूटे हुए थे। डॉ. नीरा जैन डॉ. संजय कोलानी सर्जन डॉ. बी. एल. लड्डा डॉ. के. के. डंगयेह डॉ. डॉ. परमजीत सिंह अशोक नारायणा को मूल रूप से एस. एच. ओ., पुलिस थाना गंज को आई. आर. □ □ .839/921 □ □ □ संख्या 2 और 3 की निरंतरता में अग्रेषित किया गया है और चोट संख्या 1 गंभीर (खतरनाक) जन्मजात है। • जी अकील चिश्ती (ए-3) की चोट की रिपोर्ट इस प्रकार है: "एम. एस. डब्ल्यू. □ में प्रवेश, समय-

शाम 5:45 बजे की तारीख-14.4.1992,839/92 चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग,  
राजस्थान, जयपुर

एक चोट रिपोर्ट प्रपत्र श्री अकील चिश्ती पुत्र श्री जमील चिश्ती की चोट रिपोर्ट, आयु 24 वर्ष, जाति-मुस्लिम, पुलिस निवासी रिपोर्ट संख्या. दिनांकित. संलग्न। हर्ट नोनल का प्रकृति आकार जो एक्स-रे की पहचान करता है प्रत्येक पर चोट या कटाव के विवरण के निशान का प्रकार, चोट जो गंभीर हथियार से ताजबीज़-लायनवाउंड को घायल करती है, आंशिक रूप से चोट आदि के इंचों को कुचलने का कारण बनती है। लंबाई, बाँड़ीविड्थैडदेवथ 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेब घाव 4 1 सेमी □. तेज एम 3 1 सेमी फ़ेशबैक!पीछे का क्षेत्रऑब्लीक्यूली प्लेसड ओपिनियन एनार बैक एंड्रियाहट हील के बाहरी हिस्से पर पुराना स्कार्सर्जिकल ध्यान देंएसडी/- 'डॉ. वी. डी. काविया, एम. डी. रीडर, मेडिकल विभाग के प्रमुख □□□□□□□. मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अजमेर' अकील चिश्ती के ऑपरेटिव ध्यान दें्स इस प्रकार हैं:"ऑपरेटिव नोट्स रोगी का नामअकील □□□□□ □□। 9740 तारीख:14/4/92 जी सर्जिकल पैथोलॉजी-घाव को वापस काटें एनेस्थीसिया-□□ □ □□□□□□-घाव की मरम्मत।टिप्पणियाँ:एच लकड़ी क्षेत्र में मध्य रेखा के पास पीछे की ओर एक घाव था जो मांसपेशियों में गहरा था और परतों में सिलवाया गया था।डॉ. मोहम्मद खलील चिश्ती बनाम 799 राजस्थान राज्य [पी. सतशिवम, जे.] डॉ. नीरा जैन। संजय कोलानीएसडी/सर्जन डॉ। बी. एल. लड्डा डॉ. के. के. डंगयेह डॉ. डॉ. परमजीत सिंह अशोक नारायणा (डॉ. के. के. डंगयेह) आई. आर. □□.840/921□□□□ नंबर 1 की निरंतरता में मूल रूप से एस. एच. ओ., पुलिस थाना गंज को अग्रेषित प्रकृति में सरल है।"19.फारुख चिश्ती और अकील चिश्ती की उपरोक्त 'चोट रिपोर्ट' के साथ-साथ उनके संबंधित 'ऑपरेटिव नोट्स' स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि दोनों को एक ही घटना में 14.04.1992 पर चोटें आईं।फारुख से संबंधित रिपोर्ट से पता चलता है कि धारदार हथियारों के उपयोग के कारण उन्हें छुरा घोंपने से चोटें आईं।उनसे संबंधित ऑपरेटिव नोट्स से यह भी पता चलता है कि चोट संख्या 2 और 3 सरल हैं

और चोट संख्या। 1 प्रकृति में गंभीर (खतरनाक) है।अकील चिश्ती से संबंधित चोट की रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि उसे धारदार हथियार के उपयोग से छुरा घोंपने से चोटें आई थीं।यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री में सभी प्रासंगिक पहलू, अर्थात् दो अभियुक्त अपीलार्थियों द्वारा की गई चोटें उपलब्ध हैं, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि उन्होंने उन चोटों को कैसे बनाए रखा।दूसरे शब्दों में, अभियोजन पक्ष घटना की उत्पत्ति को साबित करने में विफल रहा और वास्तव में उन्होंने उसी 20 को दबा दिया।लक्ष्मी सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य, (1976) 4 एस. सी. सी. 394 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि: ..... यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अपराध को गलत ठहराते हुए, सबूत अधिक होता है, और इसलिए एक हत्या के मामले में जहां एक आरोपी को उसी घटना के दौरान चोटें लगी हैं, अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसी चोटों का स्पष्टीकरण न देना अभियोजन पक्ष के मामले में एक स्पष्ट दोष है और यह दर्शाता है कि घटना की उत्पत्ति और उत्पत्ति को जानबूझकर दबा दिया गया था जिससे उनका प्रतिरोधी निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष घटना के सत्य विरोध के साथ सामने नहीं आया है। यह स्पष्ट है कि जहां अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर लगी चोटों की व्याख्या करने में विफल रहता है, वहां दो परिणाम सामने आते हैं:(1) कि अभियोजन पक्ष के गवाह का साक्ष्य असत्य है और (2) कि चोटें अपीलार्थियों द्वारा की गई याचिका को संभव बनाती हैं।हत्या के मामले में, घटना के समय या विवाद के दौरान आरोपी को लगी चोटों का विवरण न देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति है जिससे अदालत निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकती है:"(1) कि अभियोजन पक्ष ने घटना की उत्पत्ति और उत्पत्ति को दबा दिया है और इस प्रकार सी सत्य-परिवर्तन प्रस्तुत नहीं किया है; (2) जिन गवाहों ने अभियुक्त के व्यक्ति पर चोटों की उपस्थिति से इनकार किया है, वे भौतिक बिंदु पर झूठ बोल रहे हैं और इसलिए उनका साक्ष्य अविश्वसनीय है; (3) कि यदि कोई बचाव संस्करण है जो अभियुक्त के व्यक्ति पर चोटों की व्याख्या करता है तो इसे अभियोजन पक्ष पर संदेह

करने के लिए संभावित रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

21. यह आगे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के व्यक्ति पर चोटों की व्याख्या करने में चूक बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जहां साक्ष्य इच्छुक या शत्रुतापूर्ण गवाहों का होता है या जहां बचाव पक्ष एक ऐसा संस्करण देता है जो अभियोजन पक्ष के साथ प्रायिकता में प्रतिस्पर्धा करता है। हालांकि, ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ अभियोजन पक्ष द्वारा चोटों का स्पष्टीकरण न दिए जाने से अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। यह सिद्धांत उन मामलों में लागू होगा जहां अभियुक्त द्वारा की गई चोटें मामूली और सतही हैं या जहां साक्ष्य इतना स्पष्ट और ठोस है कि यह चोटों की व्याख्या करने के लिए अभियोजन की ओर से चूक के प्रभाव से अधिक है।

22. वामन और अन्य बनाम में। महाराष्ट्र राज्य, (2011) 7 एस. सी. सी. 295 जिसमें हम में से एक (पी. सतशिवम, जे.) ने उन्हीं सिद्धांतों को दोहराया और कहा कि:

"36. आम तौर पर, अभियोजन पक्ष किसी अभियुक्त पर प्रत्येक चोट की व्याख्या करने के लिए बाध्य नहीं है, भले ही चोटें घटना के दौरान हुई हों, यदि चोटें प्रकृति में छोटी हैं, हालांकि, यदि अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों में से किसी एक पर गंभीर चोट की व्याख्या करने में विफल रहता है, जो उसी घटना के दौरान हुई थी, तो निश्चित रूप से अदालत अभियोजन पक्ष के मामले को इस आधार पर थोड़ा संदेह के साथ देखती है कि अभियोजन पक्ष ने घटना के सही संस्करण को दबा दिया है। हालांकि, अगर सबूत स्पष्ट, ठोस और विश्वसनीय है तो मृतक या आरोपी को लगी कुछ चोटों का स्पष्टीकरण न देना पूरे अभियोजन मामले को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है।

23. श्री तुलसी, 2012 दण्डिक अपीलिय सं 635 में अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यह इंगित करते हुए तर्क दिया कि चूंकि शिकायतकर्ता तलवार, हॉकी

स्टिक और फेंके गए पत्थरों से लैस हमलावर थे, इसलिए अपीलार्थी/अभियुक्त निजी बचाव के अधिकार का लाभ उठाने के हकदार हैं, जिसके लिए उन्होंने इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों पर भरोसा किया।

24. रघुबीर सिंह अन्य राजस्थान राज्य और अन्य में। (2011) 12 धारा 235, पैरा 16 में निम्नलिखित निष्कर्ष को लागू किया गया है:

"16.रूपर बताए गए तथ्यों के आलोक में, यह देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि दोनों पक्ष युद्ध करने के लिए आए थे, उचित प्रतीत होती है क्योंकि यह साक्ष्य की सराहना पर एक मूल्यांकन है जिसे स्पष्ट रूप से गलत नहीं कहा जा सकता है ताकि इस अदालत के हस्तक्षेप को आमंत्रित किया जा सके। गजानंद मामले में यह टिप्पणी कि दोनों पक्षों को एक स्वतंत्र लड़ाई के भीतर लाने के लिए सशस्त्र और युद्ध आदेशने के लिए तैयार होना पड़ता है, वर्तमान मामले में लागू किया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक आरोपी अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए उत्तरदायी होगा।

25. कृष्णन बनाम तमिलनाडु राज्य, (2006) 11 एस. सी. सी. 304 में निम्नलिखित सिद्धांतों पर भरोसा किया गया है: "15. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि यह स्थापित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर है कि उसकी कार्रवाई निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग करने के लिए थी। याचिका को या तो निष्पक्ष साक्ष्य देकर या अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से ही स्थापित किया जा सकता है, लेकिन यह अटकलों या केवल अनुमानों पर आधारित नहीं हो सकता है। अभियुक्त को याचिका को स्पष्ट रूप से लेने की आवश्यकता नहीं है। वह अपनी याचिका में सफल हो सकता है यदि वह अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य या अन्य साक्ष्यों से यह सामने लाने में समर्थ हो कि स्पष्ट आपराधिक कार्य उसके द्वारा निजी बचाव के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए किया गया था। उसे ऐसी परिस्थितियों का पता लगाना चाहिए जो उसके दिमाग में

एक आशंका पैदा कर सकती थीं कि अगर वह निजी रक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करता है तो उसे मौत या गंभीर चोट लग सकती है। साक्ष्य अधिनियम की खंड 105 (दंड संहिता की खंड 96 से 106 के साथ पढ़ें) के तहत एक आरोपी पर निजी बचाव की याचिका स्थापित करने के लिए लगाए गए बोझ और मामले को साबित करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की खंड 101 के तहत अभियोजन पक्ष पर डाले गए बोझ के बीच एक स्पष्ट अंतर है। अभियुक्त पर बोझ उतना भारी नहीं है जितना कि अभियोजन पक्ष पर है। जबकि अभियोजन पक्ष को अपने मामले को एक उचित संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता होती है, अभियुक्त संभावना की प्रधानता स्थापित करके अपनी जिम्मेदारी निभाता है (प्रताप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सलीम जिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और मोहिंदर पाल जॉली बनाम पंजाब राज्य)।

16. सेकर बनाम राज्य में इस न्यायालय ने कहा: (एस. सी. सी. पी. 355) "निजी बचाव के अधिकार की याचिका अनुमानों और अटकलों पर आधारित नहीं हो सकती है। यह विचार करते हुए कि क्या किसी अभियुक्त के लिए निजी बचाव का अधिकार उपलब्ध है, यह प्रासंगिक नहीं है कि उसे हमलावर को गंभीर और प्राणघातक चोट पहुँचाने का मौका मिल सकता है या नहीं। यह पता लगाने के आदेश कि निजी बचाव का अधिकार उपलब्ध है या नहीं, अभियुक्त द्वारा प्राप्त चोटें, उसकी सुरक्षा के आदेश खतरे की निकटता, अभियुक्त द्वारा की गई चोटें और क्या अभियुक्त के पास सार्वजनिक अधिकारियों का सहारा लेने का समय था, ये सभी प्रासंगिक कारक हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। क्या परिस्थितियों के एक विशेष समूह में, निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्धारित किया जाने वाला तथ्य का प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न के निर्धारण के लिए संक्षिप्त सार में कोई परीक्षण निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तथ्य के इस प्रश्न को निर्धारित करते हुए, न्यायालय को आसपास की सभी परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। अभियुक्त के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह इतने शब्दों में गुहार लगाए कि

उसने आत्मरक्षा में काम किया। यदि परिस्थितियों से पता चलता है कि निजी बचाव के अधिकार का वैध रूप से प्रयोग किया गया था, तो अदालत इस तरह की याचिका पर विचार करने के लिए तैयार है। किसी मामले में, अदालत इस पर विचार कर सकती है, भले ही आरोपी ने इसे नहीं लिया हो, अगर यह रिकॉर्ड पर सामग्री से विचार करने के लिए उपलब्ध है।" (जोर दिया गया)

17. उपरोक्त कानूनी स्थिति को रिज़ान बनाम छत्तीसगढ़ राज्य में दोहराया गया था। इस न्यायालय के कई निर्णयों के विस्तृत संदर्भ के बाद, इस न्यायालय ने निजी बचाव की याचिका की प्रकृति और इसके समर्थन में सबूत की मात्रा को संक्षेप में प्रस्तुत किया, इस प्रकार: (एस. सी. पीपी. 670-71, पैरा 13)

"साक्ष्य अधिनियम, 1872 की खंड 105 के तहत, सबूत का भार अभियुक्त पर है, जो आत्मरक्षा की याचिका स्थापित करता है। और, सबूत की अनुपस्थिति में, अदालत के लिए आत्मरक्षा की याचिका की सच्चाई को खारिज करना संभव नहीं है। अदालत ऐसी परिस्थितियों की अनुपस्थिति में को मान लेगी। यह अभियुक्त के लिए है कि वह या तो स्वयं सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करके या अभियोजन पक्ष के लिए जांचे गए गवाहों से आवश्यक तथ्यों को प्राप्त करके आवश्यक सामग्री को रिकॉर्ड पर रखे। निजी बचाव के अधिकार की याचिका लेने वाले अभियुक्त को साक्ष्य बुलाने की आवश्यकता नहीं है; वह अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से ही उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में अपनी याचिका स्थापित कर सकता है। ऐसे मामले में प्रश्न अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के सही प्रभाव का आकलन करने का प्रश्न होगा, न कि अभियुक्त द्वारा कोई बोज़ उठाने का प्रश्न। जब निजी बचाव के अधिकार को चुनौती दी जाती है, तो बचाव पक्ष को एक उचित और संभावित परिवर्तन होना चाहिए जो अदालत को संतुष्ट करता है कि आरोपी द्वारा किया गया नुकसान या तो हमले को रोकने के लिए या आरोपी की ओर से आगे की उचित आशंका को रोकने के लिए आवश्यक था। आत्मरक्षा याचिका स्थापित करने का भार अभियुक्त पर है और अभिलेख पर सामग्री के आधार पर उस याचिका के पक्ष

में संभावनाओं की प्रधानता दिखाने से बोज़ कम हो जाता है।

अभियुक्त को उचित संदेह से परे निजी बचाव के अधिकार के अस्तित्व को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि जैसा कि एक दीवानी मामले में है कि संभावनाओं की प्रधानता उनकी याचिका के पक्ष में है।" (जोर दिया गया) "

26. बाबुला/भगवान खंडारे और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2005) 10 एस. सी. सी. 404 के मामले में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि घटना के समय या विवाद के दौरान अभियुक्त को लगी चोटों का विवरण न देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति है। यह भी माना गया कि आत्मरक्षा का अधिकार एक बहुत ही मूल्यवान अधिकार है, जो एक सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करता है और इसे संकीर्ण रूप से नहीं लिया जाना चाहिए।

27. यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को लगी चोटों की व्याख्या करे और स्वीकार्य सामग्री प्रस्तुत करके घटना की उत्पत्ति को स्थापित करे। हाथ के मामले में, हम पहले ही बता चुके हैं कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि उसी घटना के दौरान फारुख (ए-4) और अकील (ए-3) को भी चोटें आईं। वास्तव में, फारुख को धारदार हथियार के उपयोग से गंभीर चोट लगी। हालाँकि, अभियोजन पक्ष द्वारा इन चोटों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया गया था।

28. श्री जसबिर सिंह मलिक, राज्य के विद्वान अधिवक्ता, इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा करते हुए मिट्टू/ए. एफ. और अन्य बनाम में रिपोर्ट किए गए। मध्य प्रदेश राज्य, (1975) 3 एस. सी. सी. 529 ने प्रस्तुत किया कि प्रति मामले में साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह सच है कि उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उसने उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को स्वीकार नहीं किया है, जिसने न केवल अपीलार्थियों और चार अन्य

अभियुक्तों के खिलाफ मामले में दर्ज निष्कर्ष पर अपना निष्कर्ष निकाला है, बल्कि गणपत, राजधर और अन्य के खिलाफ प्रति मामले में दर्ज साक्ष्य को भी ध्यान में रखा है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया मार्ग स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य था। उक्त प्रस्ताव के बारे में कोई विवाद नहीं है और वास्तव में मामले में, न तो निचली अदालत और न ही उच्च निचली अदालत ने क्रॉस मामले में दिए गए साक्ष्य पर भरोसा किया, लेकिन उन पर अलग से मुकदमा चलाया गया और वास्तव में क्रॉस मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ उच्च निचली अदालत के समक्ष अपील अभी भी लंबित हैं।

29. राज्य के वकील द्वारा जिस अन्य निर्णय पर भरोसा किया गया है, वह शंभू दास उपनाम बिजय दास और एक अन्य बनाम असम राज्य, (2010) 10 एस. सी. सी. 374 में बताया गया है, जो दर्शाता है कि यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को फिर से नहीं खोलेगा, जब तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष हैं और इसमें शामिल कानून का कोई सवाल नहीं है और निष्कर्ष विकृत नहीं है। उपरोक्त प्रस्ताव सही है। हम यह भी दोहराते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 136 किसी भी पक्ष को अपील करने का अधिकार नहीं देता है। यह इस न्यायाधीशालय को केवल उन उपयुक्त मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है जहां अवैधता या गलतफहमी या साक्ष्य पढ़ने में गलती या भौतिक साक्ष्य की अनदेखी, बहिष्कार या अवैध रूप से स्वीकार करने के परिणामस्वरूप न्यायाधीश का गंभीर दुरुपयोग हुआ है।

सारांश:

30. अभियोजन पक्ष के मामले के विश्लेषण से, निस्संदेह, साक्ष्य के दो सेट सामने आए हैं। प्रस्तुत साक्ष्य से पता चलता है कि वर्तमान अपीलों में आरोपी कुछ हद तक मृतक और उसके साथियों के हाथों सशस्त्र हमले के शिकार हैं। हमने बताया है कि

तारिक मोहम्मद (पीडब्लू-1) ने पदच्युत किया कि उसने इदरीस (मृतक) को अपने हाथ में चाकू, मोहम्मद के साथ देखा था। असलम (पीडब्लू-3), सगीर (पीडब्लू-6), शमीम (पीडब्लू-18) और अन्य लाठियों से लैस होकर फारुख (ए-4) के घर के लिए रवाना हो गए। उनके द्वारा यह भी अपदस्थ कर दिया गया कि उन्होंने इदरीस और जी अन्य लोगों को रोकने की कोशिश की लेकिन व्यर्थ। अभियोजन पक्ष की ओर से पूछताछ किए गए पुलिस कांस्टेबल भंवर सिंह (पीडब्लू-4) और भंवर लाल शर्मा (पीडब्लू-5) अपराध स्थल पर मौजूद थे। हम पहले ही इन दो गवाहों के साक्ष्य पर विचार कर चुके हैं जो स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि शिकायतकर्ता का पक्ष, यानी 1992 की प्राथमिकी संख्या 91 में आरोपी तलवार, हॉकी स्टिक आदि से लैस था और चिश्ती मंजी में घुस गया था!, गाली-गलौज की, कैदियों पर पत्थर फेंके और खलील चिश्ती (ए-2) और फारुख (ए 4) को मारने का आह्वान किया। इन व्यक्तियों ने यह भी बयान दिया कि इदरीस (मृतक) और 1992 की प्राथमिकी संख्या 91 में आरोपी घटना में हमलावर थे। पीडब्लू 4 और 5 को ट्रायल कोर्ट द्वारा स्वतंत्र गवाहों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यहां तक कि अपने साक्ष्य में भी, उन्होंने खलील (ए-2) को किसी विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। एम. ए. तारिक 1. (पीडब्लू-25) ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता का पक्ष अपीलार्थियों पर हमला करने के इरादे से उनके घर में जबरन घुस गया।

31. मोहम्मद.असलम (पीडब्लू-3), सगीर अहमद (पीडब्लू-6), सईद जावेद (पीडब्लू-13) और शमीम (पीडब्लू-18) से घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में पूछताछ की गई। मान लीजिए, उनमें से किसी ने भी फारुख (ए-डी 4) और अकील (ए-3) को लगी चोटों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। हम इन व्यक्तियों से संबंधित चोट की रिपोर्ट के बारे में पहले ही जानकारी दे चुके हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति में, हमारा विचार है कि वे घटना की वास्तविक उत्पत्ति को दबाने के दोषी हैं। निचली अदालत ने तोते जैसे संस्करण का वर्णन करने के लिए पीडब्लू-18 के साक्ष्य की भी निंदा की थी और किए गए कई सुधारों की ओर भी इशारा

किया था।

32. सामग्री के विश्लेषण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत घटना के दो संस्करण एक दूसरे के साथ असंगत हैं। ऐसी स्थिति में जब अभियोजन पक्ष साक्ष्य के दो सेटों का नेतृत्व करता है, जिनमें से प्रत्येक विरोधाभासी है और दूसरे पर हमला करता है और इसे अविश्वसनीय दिखाता है, तो परिणाम यह होगा कि अदालत के पास कोई विश्वसनीय और भरोसेमंद सबूत नहीं बचेगा, जिसके आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि हो सकती है। यद्यपि अभियुक्त को ऐसी स्थिति का लाभ होगा और अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित वकील ने सभी आरोपों से अपीलार्थियों को दोषमुक्ति का अनुरोध किया, उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जिन पर हमने पहले ही चर्चा की है, हमारा विचार है कि प्रत्येक अभियुक्त को प्रत्येक अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका या भाग को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत दायित्व के साथ लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, दोनों पक्षों को उनके व्यक्तिगत कृत्यों के लिए दोषी ठहराया जा सकता है और आम तौर पर किसी भी पक्ष को निजी बचाव का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं है और वे अपने-अपने कृत्यों के लिए दोषी होंगे।

33. खलील (ए-2) की भूमिका के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उसके खिलाफ भा.दं.सं. सी. की खंड 34 लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहां तक कि स्वतंत्र गवाह भी।, पीडब्लू 4 और 5 बी किसी भी स्पष्ट कार्य के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं।

34. जैसा कि अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने ठीक ही बताया है, मामले और प्रति-मामले के आलोक में, यह बातों की योग्यता में होगा कि 2011 के सत्र मामले संख्या 157 और 2011 के सत्र मामले संख्या 178 में दोषियों द्वारा पसंद की गई अपील के खिलाफ अपीलार्थियों द्वारा दायर संबंधित अपीलों की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा एक साथ की जानी चाहिए थी और उनका निपटारा किया जाना चाहिए था। दुर्भाग्य से,

उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह का उपाय नहीं अपनाया गया है और हमें सूचित किया गया है कि

दूसरी अपील (सीआरएल। 2011 का सत्र मामला संख्या 178 से संबंधित अपील संख्या 131) अभी भी उच्च न्यायालय की फाइल पर लंबित है।

35. अन्य अभियुक्तों, यासिर चिश्ती (ए-1) और अकील चिश्ती (ए-3) पर आते हुए, उन्हें स्वीकार्य सामग्री के बिना भा.दं.सं. सी. की खंड 34 की सहायता से उनके द्वारा किए गए व्यक्तिगत कृत्यों के लिए दंडित और दायित्व निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने उल्लेख किया कि इन अपीलार्थियों के पास एक पिस्तौल थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या किसी को उस पिस्तौल की गोली लगी थी और इस बात का कोई विशिष्ट सबूत नहीं मिला कि गोली उनके हाथ में पिस्तौल से निकली थी। यहां तक कि मोहम्मद भी।एफ मुखबिर असलम (पीडब्लू-3) ने अदालत के समक्ष कहा कि इन अपीलकर्ताओं ने अपनी पिस्तौल से गोलीबारी की लेकिन उस आग से किसी को चोट नहीं लगी।

36. जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, पीडब्लू 4 और 5-पुलिस कांस्टेबलों के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि शिकायतकर्ता का दल तलवार और हॉकी स्टिक से लैस था और गाली-गलौज और पथराव कर रहा था। सगीर (पीडब्लू-6) ने हालांकि यह बयान दिया कि वर्तमान अपीलार्थियों के पास एक रिवॉल्वर थी और उन्होंने उस पिस्तौल से गोली चलाई, यह बताए बिना कि क्या इस तरह की गोलीबारी से कोई घायल हुआ था। पीडब्लू-4-अभियोजन पक्ष के गवाहों में से एक, पुलिस कांस्टेबल ने इनकार किया था:- वास्तव में, इन अपीलार्थियों के पास रिवॉल्वर होने के कारण, पीडब्लू 4 और 5 ने अपीलार्थियों, यानी ए-1 और ए-3 द्वारा किए गए किसी भी प्रदर्शन का श्रेय नहीं दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि शिकायतकर्ता का पक्ष सशस्त्र हमलावर था। यह इंगित करना प्रासंगिक है कि उसी दिन 2001 के सत्र मामला संख्या 178 में, सूचना

देने वाले को पांच अन्य सह-अभियुक्तों के साथ भा.दं.सं. सी. की खंड 307,324,326,452 और 148 के साथ भा.दं.सं. सी. की खंड 149 के तहत दोषी ठहराया गया था। हम इस बात से भी संतुष्ट हैं कि यद्यपि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने कहा है कि इन अपीलार्थियों के पास रिवॉल्वर थे, पीडब्लू 4 और 5 के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि शिकायतकर्ता का पक्ष हमलावर था और वर्तमान अपीलार्थियों के पास कोई रिवॉल्वर नहीं थी।

37. ऊपर बताए गए तथ्यों के आलोक में, विशेष रूप से, त्रिपोलिया पुलिस चौकी, पी. एस. गंज से जुड़े पीडब्लू 4 और 5-पुलिस कांस्टेबलों के साक्ष्य और सामग्री से पता चलता है कि मृतक और शिकायतकर्ता का दल भी तलवार और हॉकी स्टिक से लैस था। ए-1 और ए-3 की रिवॉल्वरों से गोली चलने के साक्ष्य का अभाव में और वर्तमान अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप लगाने वाले पीडब्ल्यू 3,6,13 और 18 के बयान को देखते हुए, मामले को एक स्वतंत्र लड़ाई के भीतर लाने के लिए दोनों पक्षों को सशस्त्र होना होगा और वर्तमान मामले में युद्ध आदेशने के लिए तैयार रहना होगा, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक अभियुक्त अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए उत्तरदायी होगा।

निष्कर्ष:

38. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, भले ही हम अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य को प्रतिग्रहण करना करते हैं कि ए-2 के पास तलवार थी और पीडब्लू-3 को उसके कहने पर चोटें आईं, उसके व्यक्तिगत कार्य पर विचार करते हुए, उसे केवल भा.दं.सं. की खंड 324 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है और उसकी उम्र और इस तथ्य पर ध्यान दें जा सकता है कि वह मुकदमे के दौरान 14.04.1992 से 09.05.1992 तक और फिर से 31.01.2011 से 12.04.2012 (लगभग एक वर्ष और चार महीने) तक हिरासत में था, हमें लगता है कि न्यायाधीश के उद्देश्यों को सजा को पहले से गुजर चुकी अवधि में बदलकर पूरा किया जाएगा। दोषसिद्धि और सजा को ऊपर

उल्लिखित सीमा तक संशोधित किया गया है और 2012 दाण्डिक अपीलिय सं 634 का तदनुसार निपटारा किया गया है।

39. दिनांक 10.05.2012 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने डॉ. मोहम्मद खलील चिश्ती-2012 के संख्या 634 में पाकिस्तान के नागरिक होने के नाते-अपीलकर्ता या उनके नामित व्यक्ति को रु। उस तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय की पंजीकरण के साथ प्रतिभूति के रूप में 5 लाख रुपये और उपरोक्त शर्त को पूरा करने पर, अपीलार्थी को भारत छोड़ने और अपने गृह देश, यानी पाकिस्तान जाने की अनुमति दी गई थी। हमें सूचित किया जाता है कि उक्त शर्त का पालन किया गया है और रु। 5 लाख जमा किए गए। आई. डी. 1 के एक अन्य आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने पंजीकरण को निर्देश दिया कि अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई राशि को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में ब्याज वाले खाते में शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए निवेश किया जाए। हमारे इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि आगे किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, पंजीकरण को डॉ. मोहम्मद खलील चिश्ती या उनके नामित व्यक्ति को उक्त राशि तुरंत वापस करने का निर्देश दिया जाता है। यह भी निर्देश दिया जाता है कि यदि अपीलकर्ता का पासपोर्ट या कोई अन्य दस्तावेज निचली अदालत या भारत सरकार के किसी अन्य प्राधिकारी की हिरासत में है, तो उन्हें उसे वापस करने का निर्देश दिया जाता है और वह बिना किसी प्रतिबंध के अपने देश लौटने के लिए स्वतंत्र है। उनकी आयु और विद्या सम्बन्धी योग्यता आदि ध्यान दें में रखते हुए, इस तरह के पाठ्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार के संबंधित विभाग को आवश्यक वीजा जारी करने और उनके देश में उनकी सुचारु वापसी के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करने का निर्देश दिया जाता है।

40. 2012 दाण्डिक अपीलिय सं 635 में अपीलकर्ता यासिर चिश्ती (ए-1) और अकील चिश्ती (ए-3) के संबंध में साक्ष्य और निष्कर्ष के आलोक में, उनके व्यक्तिगत कृत्यों पर ध्यान देते हुए, उन्हें केवल भा.दं.सं. सी. की खंड 324 के तहत दोषी ठहराया

जा सकता है और इस तथ्य ध्यान दें में रखते हुए कि ए-1 और ए-3 ने क्रमशः लगभग 11 और 10 महीने की सजा काट ली है, वही पर्याप्त होगा और आगे किसी कारावास की आवश्यकता नहीं है, इसलिए, दोनों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता नहीं है।

41. उपरोक्त संशोधन के साथ, दोनों अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

के. के. टी.

अपीलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।